जोन क्रांतिकारी जनताना सरकार समन्वय कमेटी
दंडकारण्य

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांकः 30 जनवरी, 2021

किसान विरोधी एवं देशद्रोही तीन कृषि कानूनों को वापस लेने तक आंदोलन को जारी रखें!

बस्तर महान भूमकाल की लड़ाकू विरासत को ऊंचा उठाते हुए, किसान आंदोलन के समर्थन में 10 फरवरी को संकल्प दिवस मनावें!

कृषि क्रांति ही किसान समस्याओं का सही व एकमात्र समाधान है!

केंद्र की ब्राह्मणीय हिंदुत्व फासीवादी भाजपा की मोदी सरकार द्वारा सितंबर 2020 में लाए गए किसान विरोधी, जन विरोधी एवं देशद्रोही तीन कृषि कानूनों – कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य (संवर्धन एवं सरलीकरण) कानून 2020, कृषक (सशक्तीकरण व संरक्षण) कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार कानून 2020, आवश्यक वस्तु (संसोधन) कानून 2020 को वापस लेने की मांग को लेकर पिछले दो महीनों से भी ज्यादा समय से आंदोलनरत देश के किसानों एवं उनका नेतृत्व करने वाले किसान संयुक्त मोर्चे का दंडकारण्य जोन क्रांतिकारी जनताना सरकार समन्वय कमेटी क्रांतिकारी अभिनंदन व अभिवादन करती है.

लगातार विस्तार व तेज होते देशव्यापी किसान आंदोलन को कुचलने लाल किला षड्यंत्र रचकर केंद्र सरकार ने 26 जनवरी को उस पर अमल किया जिसकी हमारी जनताना सरकार कड़ी निंदा करती है. जब 26 जनवरी को मोर्चा के आह्वान पर 8 लाख ट्रैक्टरों के साथ 20 लाख किसान दिल्ली कूच कर रहे थे तब केंद्र सरकार के निर्देश पर दिल्ली पुलिस ने किसान नेताओं व किसानों पर अश्रु गैस और लाठी चार्ज का प्रयोग किया जिससे सैकड़ों किसान घायल हुए. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पुलिस की गोली से एक किसान की मौत भी हुई. इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस ने किसानों व किसान नेताओं पर 2000 से अधिक अवैध केस दर्ज किए. शासन–प्रशासन से अनुमति प्राप्त कर, शांतिपूर्ण व जनवादी तरीके से आंदोलनरत किसानों पर केंद्र सरकार द्वारा बर्बर दमन के प्रयोग की हमारी जनताना सरकार घोरतम शब्दों में भर्त्सना करती है.

अंबानी, अदानी, दमानी, वालमॉर्ट, टीसीआई जैसी देशी, विदेशी कॉरपोरेट कंपनियों को मुनाफा पहुंचाने एवं जमीन, उत्पादन, भंडारण, बिक्री सभी पर उनका पूर्ण नियंत्रण स्थापित कराने के लिए ही लाए गए उपरोक्त तीनों कानून दरअसल देश की खेती और किसानों को बर्बाद करने वाले हैं. देश को खाद्यान्न के लिए भी पराधीन बनाने वाले हैं. ये कानून दरअसल देश की जनता के साथ धोखा, साजिश व गद्दारी है.

साम्राज्यवाद–दलाल नौकरशाही पूंजीवाद–सामंतवाद विरोधी वर्ग संघर्ष–जनयुद्ध के जरिए दंडकारण्य में अंकुरित जनता की नवजनवादी राज्यसत्ता का प्रतिनिधित्व करने वाली पंचायत, एरिया और डिविजन स्तर की क्रांतिकारी जनताना सरकारों (रिवोल्यूशनरी पीपुल्स कमेटि–आरपीसी) के दंडकारण्य व्यापी समन्वय के लिए गठित दंडकारण्य जोन क्रांतिकारी जनताना सरकार समन्वय कमेटी वर्तमान किसान आंदोलन का भरपूर समर्थन करती है, केंद्र सरकार की किसान विरोधी, जन विरोधी व देशद्रोही तीन कृषि कानूनों को वापस लेने तक आंदोलन को जारी रखने का आह्वान करती है. 1910 के बस्तर महान भूमकाल की लड़ाकू विरासत को अपनाते हुए उसकी 111वीं वर्षगांठ के अवसर पर आगामी 10 फरवरी को किसान आंदोलन को जीत के मुकाम तक पहुंचाने के संकल्प दिवस मनाने हमारी सरकार देश के संघर्षरत किसानों सहित तमाम किसानों का आह्वान करती है. किसान आंदोलन के समर्थन में आगे आने तमाम मजदूरों, देशभक्त, जनवादी व प्रगतिशील ताकतों से अपील करती है. दंडकारण्य में कार्यरत हमारी तमाम स्तरों की क्रांतिकारी जनताना सरकारों, जन संगठनों व जनता का आह्वान करती है कि वे किसान आंदोलन के समर्थन में जनता को गोलबंद करें.

देश के वर्तमान कृषि संकट और किसानों की तमाम समस्याओं का एकमात्र व सही हल है, नव जनवादी क्रांति जिसकी धुरी सिर्फ और सिर्फ कृषि क्रांति ही है. इसलिए हमारी सरकार संघर्षरत किसान भाइयों एवं बहनों से अपील करती है कि वे साम्राज्यवाद–दलाल नौकरशाही पूंजीवाद–सामंतवाद विरोधी वर्ग संघर्ष–जनयुद्ध के रास्ते कृषि क्रांति के जरिए नवजनवादी क्रांति को सफल बनाने की दिशा में आगे बढ़ें.

सुक्कू

(सुक्कु लेकाम)
प्रभारी,
जोन क्रांतिकारी जनताना सरकार समन्वय कमेटी,
दंडकारण्य